पुरस्कार की तारीख से तीस दिनों के भीतर उनके समक्ष आवेदन करना होगा, और यह अधिकार उन व्यक्तियों तक ही सीमित है जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए आवेदन नहीं किया है। यदि ये शर्तें पूरी होतीं, तो याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 28 ए के तहत प्रदान किए गए उपाय का लाभ उठा सकते थे। उस स्थिति में, धारा 25 उनके लाभ को सुनिश्चित करेगी। कोई भी अन्य दृष्टिकोण विनाशकारी परिणामों को जन्म देगा जो विधायिका द्वारा अपेक्षित नहीं है।"

(5) चूंकि याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 28-ए के तहत रेमेडियोव को साबित नहीं किया, इसलिए निष्पादन न्यायालय ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया है क्योंकि यह इस तरह से बनाए रखने योग्य नहीं था। परिणामस्वरूप, दोनों याचिकाएँ विफल हो जाती हैं और लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दी जाती हैं।

पहले: वी. रामास्वामी, सी.जे. और जी.आर. मजीठिया, जे.

भारत संघ और अन्य,-अपीलकर्ता।

बनाम

एलटी. कर्नल (अब मेजर) सुरजीत सिंह - प्रतिवादी।

1988 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 550

10 मार्च 1989.

भारत का संविधान, 1950-कला. 162 और 226–सेना निर्देश एल/। एस/75 2/76 द्वारा संशोधित और सेना निर्देश 31/86 द्वारा आगे संशोधित - प्रत्यावर्तन - अनुशासनात्मक आधार

पर सेना अधिकारी की कुर्की - कोर्ट मार्शल कार्यवाही लंबित - 21 दिनों के लिए कर्तव्यों का पालन न करने पर कार्यवाहक रैंक से प्रत्यावर्तन का प्रावधान करने वाले निर्देश जिसके लिए कार्यकारी पद दिया गया था - ऐसे सैन्य निर्देश बाध्यकारी - मूल पद पर प्रत्यावर्तन मान्य। माना गया कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जहां नियम मौन हैं, राज्य भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 162 के तहत अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये सेना निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के दायरे में आते हैं। 1950

आगे कहा गया कि जब याचिकाकर्ता को 15 अप्रैल, 1985 से मुख्यालय 39 मर्चेनाइज्ड ब्रिगेड से जोड़ा गया था, तो उचित अदालत की जांच के बाद कार्रवाई की गई थी और सक्षम प्राधिकारी ने निर्देश दिया था कि अपराधी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। पूछताछ में पीतल और अलमीनियम स्क्रैप की अवैध बिक्री में उनकी संलिप्तता स्थापित होने के बाद उनकी कुर्की की गई थी। इसलिए, सैन्य अधिकारियों की कार्रवाई कानूनन पूरी तरह से उचित है।

उपरोक्त सी.डब्ल्यू.पी. में माननीय श्री न्यायमूर्ति डी. वी. सहगल के दिनांक 2 जून, 1988 के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत लेटर्स पेटेंट अपील। 1987 के क्रमांक 5303 को जुर्माने सहित खारिज किया जाए।

एच. एस. बराड़. भारत सरकार के वरिष्ठ स्थायी वकील पी.एस. तेजी, अपीलकर्ता के वकील हैं। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता आर.एस. रंधावा।

फ़ैसला

जी. आर. मजीठिया, जे.

(1) यह एक विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर लेफ्टिनेंट कर्नल के कार्यवाहक रैंक के वेतन का बकाया 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ भुगतान किया जाए।

(2) तथ्य पहले: प्रतिवादी, जिसे इसके बाद याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाएगा, को 13 जून, 1963 को सशस्त्र बलों में नियुक्त किया गया था। उन्हें 9 जून, 1983 को चयन ग्रेड लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया था और तैनात किया गया था। नवगठित 18 मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री। यूनिट की कमान संभालने से पहले. मेजर सुरिंदर कुमार ने 1 मार्च, 1983 से 8 जून, 1983 तक कमांडिंग ऑफिसर के रूप में कार्य किया। उन्होंने यूनिट में कैप्टन, जे.पी.एस. सहित विभिन्न नियुक्तियाँ कीं। तूर तकनीकी अधिकारी के रूप में।

(3) 6 जनवरी, 1984 को यूनिट के दो व्यक्तियों ने कथित तौर पर पेट्रोल बैरल से भरा एक वाहन बाहर निकाला। उनका पता लगाया गया और चूंकि वे अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे सके, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ जांच शुरू की गई। विस्तृत जांच में कैप्टन जे.पी.एस. की संलिप्तता सामने आई। तूर में ईंधन की बिक्री. कैप्टन जे.पी.एस. तूर ने अपनी जान बचाने के लिए यह बयान दिया कि ईंधन मदों के हिसाब-किताब के लिए जिम्मेदार हवलदार आकस्मिक मांगों पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करता था। याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए इसी बयान को आधार बनाया गया. याचिकाकर्ता को 15 अप्रैल, 1985 से मुख्यालय 39 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड से जोड़ा गया था। इसके परिणामस्वरूप, उसे मेजर के मूल पद पर लाया गया। सेना अधिकारियों ने यह कार्रवाई सेना निर्देश एल/, एस/74 के तहत की, जिसे सेना निर्देश 2/76 द्वारा संशोधित किया गया, जिसे आगे सेना निर्देश 31/86 द्वारा संशोधित किया गया।

(4) याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि उस पर जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा और कैप्टन जे.पी.एस. के साथ संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जाएगा।

तूर को सौंपी गई चार्जशीट के आधार पर। याचिकाकर्ता ने कैप्टन जे.पी.एस. के साथ संयुक्त परीक्षण पर आपत्ति जताई। तूर के अनुसार इससे उनके बचाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी। उन्होंने इस न्यायालय से अपीलकर्ताओं को उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल का कार्यवाहक पद बहाल करने का निर्देश देने की भी मांग की।

(5) अपीलकर्ताओं ने एक संयुक्त लिखित बयान दायर किया और कहा कि याचिकाकर्ता विशेष सेना निर्देशों के अनुसार 21 दिनों की अवधि के बाद 15 अप्रैल, 1985 से मुख्यालय 39 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड से जुड़ा था। जांच में एकत्र किए गए सबूतों से पता चला कि याचिकाकर्ता एक कैप्टन जे.पी.एस. तूर ने एक साथ साजिश रची और ईंधन, पीतल स्क्रैप, एल्युमीनियम जैसे सैन्य भंडार की चोरी में शामिल हो गए, जैसा कि आरोपपत्र अनुलग्नक आर 1 में शामिल पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आरोप में बताया गया है। 1. पीतल स्क्रैप की चोरी से संबंधित 5वां आरोप वजन 3000 किलोग्राम. मूल्य रु. कैप्टन जे.पी.एस से संबंधित 87,000 अकेला तूर और छठा आरोप पीतल के स्क्रैप का वजन 3000 किलोग्राम होने का झूठा बयान देने से संबंधित है। और 2000 कि.ग्रा. जारी किए गए, - 5 मई 1983 के वाउचर का उपयोग अकेले याचिकाकर्ता से संबंधित इकाई में किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता और कैप्टन जे.पी.एस. का संयुक्त परीक्षण। तूर पर यह आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि अधिकांश आरोप सामान्य थे और इन आरोपों के सबूत के तौर पर वही सबूत पेश किए जाने थे।

(6) विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि अधिकारियों ने अलग-अलग मुकदमे के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को सही ढंग से खारिज कर दिया था और उन्हें लगा कि असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उनके द्वारा इसमें कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। लेफ्टिनेंट कर्नल के कार्यवाहक रैंक को वापस लेने से संबंधित मामले के दूसरे पहलू

पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि सेना के निर्देश जिसके तहत की गई कथित कार्रवाई में कोई कानूनी बल नहीं है। परिणामस्वरूप, कार्रवाई उचित नहीं थी।

(7) अपील के लंबित रहने के दौरान, भारत संघ के विद्वान वरिष्ठ स्थायी वकील ने हमारे ध्यान में निम्नलिखित तथ्य लाए: - "प्रतिवादी लेफ्टिनेंट कर्नल सुरजीत सिंह को कैशियर कर दिया गया और 16 सितंबर, 1988 को जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा दी गई। सामान्य न्यायालय की प्रथम कार्यवाही की पुष्टि के लिए प्रमुख को भेज दी गई है सेना कर्मचारी।"

(8) एकमात्र प्रश्न जो निर्धारण के लिए उठता है, वह यह है कि क्या लेफ्टिनेंट कर्नल का कार्यवाहक रैंक याचिकाकर्ता से सेना अनुदेश एल/एस/74 के अनुसार मुख्यालय 39 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के साथ संलग्न होने के परिणामस्वरूप उचित रूप से वापस ले लिया गया है। जैसा कि सेना निर्देश 2/76 द्वारा संशोधित किया गया है, सेना निर्देश 31/86 द्वारा आगे संशोधित किया गया है, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैं: -

'(1) जिन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया गया है, उन्हें अनुशासनात्मक मामले की जांच और प्रगति के उद्देश्य से सेना मुख्यालय या संबंधित जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ कमांड के विवेक पर, जहां आवश्यक हो, अन्य इकाइयों से जोड़ा जा सकता है। हालाँकि, इस तरह की कुर्की का आदेश केवल तभी दिया जाएगा जब उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो, न कि किसी जांच अदालत द्वारा जांच के चरण के दौरान, यहां तक कि उन अधिकारियों के लिए भी जिनका चरित्र और सैन्य प्रतिष्ठा जांच अदालत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने की संभावना है। असाधारण मामलों में, जबकि कमांडिंग ऑफिसर के रूप में उनकी नियुक्ति में अधिकारी का निरंतर प्रतिधारण वांछनीय है, उसे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के प्रारंभ में भी किसी अन्य इकाई या गठन से जोड़ा जा सकता है।

(2) कुर्की अवधि के दौरान अधिकारियों को कुर्की से ठीक पहले उनके द्वारा की गई नियुक्ति के विरुद्ध रखा जाएगा और अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने तक कोई प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा।

(3) यह सेना के निर्देशों 106/60 का स्थान लेता है।"

उपरोक्त के आलोक में इसे आगे इस प्रकार समझाया गया है:-

(a) रैंक संरचना सहित सेना की स्थायी अधिकृत स्थापना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। इस प्राधिकरण के आधार पर प्रत्येक रैंक में रिक्तियों की कुल संख्या मूल रैंक का गठन करती है। अधिकृत प्रतिष्ठान के अलावा सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट अवधि के लिए अस्थायी आधार पर कुछ वृद्धि या वृद्धि को अधिकृत करती है जिसे मौजूदा स्थिति के आधार पर समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। सेना के बढ़े हुए पूरक में उनके मूल रैंक से अधिक नियुक्तियों वाले अधिकारियों को रैंक और वेतन की सुविधा देने के लिए, कार्यवाहक रैंक की प्रणाली शुरू की गई थी। इसलिए, कार्यवाहक रैंक उस अवधि के लिए स्वीकार्य है जब अधिकारी वास्तव में ऐसी नियुक्ति कर रहा है और कर्तव्यों का पालन कर रहा है। प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियुक्ति के वास्तविक त्याग और कार्यवाहक रैंक के त्याग के बीच 21 दिनों की एक निश्चित कुशन अवधि निर्धारित की गई है। जैसे कि जब कोई अधिकारी अपने अनुलग्नक या अनुशासनात्मक आधार या अस्पताल में भर्ती होने के कारण बीमारी के कारण इक्कीस दिनों के लिए किसी विशेष नियुक्ति में अप्रभावी हो जाता है, तो वह कार्यवाहक पद छोड़ देता है क्योंकि वह अब उन कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है जिसके लिए उसे दिया गया था। अभिनय रैंक.

(b) जब किसी मामले में किसी अधिकारी की संलिप्तता स्थापित हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, तो उसे जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही की सुविधा के लिए किसी अन्य मुख्यालय या इकाई से जोड़ दिया जाता है। यह मुख्य रूप से अनुशासन के हित में और गवाह पर अनुचित दबाव डालने के साथ-साथ सबूतों के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से तब प्रासंगिक होता है जब संबंधित अधिकारी कमांडिंग ऑफिसर होता है जिसके पास यूनिट का समग्र प्रभार होता है।

(c) याचिकाकर्ता के मामले में, उन्हें जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित रहने तक मुख्यालय 39 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड से संबद्ध कर दिया गया था, इस प्रकार उन्होंने 15 अप्रैल 85 से मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट के 18वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में कार्य करना बंद कर दिया। तदनुसार 21 दिनों की अवधि के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। 06 मई 85 से प्रभावी लेफ्टिनेंट कर्नल का कार्यवाहक रैंक।" विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के दावे को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ स्वीकार कर लिया: -

“यह भी विवाद में नहीं है कि अधिनियम, नियमों और विनियमों में इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है कि जहां किसी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही / सामान्य कोर्ट मार्शल कार्यवाही शुरू की जाती है और वह एक कार्यकारी रैंक रखता है तो उसे उसके मूल पद पर वापस कर दिया जाना चाहिए पद। कोर्ट मार्शल की कार्यवाही लंबित होने के कारण अभिनय रैंक से वास्तविक रैंक में प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप दंडात्मक परिणाम होते हैं। जिन प्रशासनिक निर्देशों के पास कोई वैधानिक बल नहीं है, उन्हें ऐसे परिणाम लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह एक अधिकारी में निहित अधिकार को छीन लेता है।"

इन टिप्पणियों का कानून द्वारा समर्थन नहीं किया जा सकता। इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (1) में निम्नानुसार निर्धारित किया गया था: -

> "यह सच है कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा वैधानिक नियमों में संशोधन या उन्हें प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है, लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप हैं तो सरकार अंतराल को भर सकती है और नियमों को पूरक कर सकती है और निर्देश जारी कर सकती है जो पहले से बनाए गए नियमों के साथ असंगत नहीं हैं।"

इस मामले में आगे कहा गया:-

> “राज्य सरकार के पास उन सभी मामलों के संबंध में कार्यकारी शक्ति है, जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य सरकार के पास एसएच के संबंध में कार्यकारी शक्ति होगी। 7, सूची II प्रविष्टि 41, राज्य लोक सेवाएँ, और कला की शर्तों में कुछ भी नहीं है। संविधान का 309 जो कला के तहत कार्य करने की कार्यपालिका की शक्ति को कम करता है। संविधान के 162 बिना कानून के।”

(9) वहां मुझे संदेह है कि राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सेना के ये निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के दायरे में आते हैं। इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने संदर्भित टिप्पणियाँ देने में गलती की है

(1) ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1910.

सुप्रा. विद्वान एकल न्यायाधीश रोमेश चंदर बनाम जी.ओ.सी. उत्तरी कमान और अन्य (2) द्वारा जिस प्राधिकार पर भरोसा किया गया, उसका वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव

नहीं है। उस मामले में, सेना के निर्देश, जो चुनौती के अधीन थे, विवाद के समान नहीं थे। विद्वान न्यायाधीश ने पदोन्नति रद्द करने के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उनके समक्ष यह स्वीकार किया गया था कि जिस समय पदोन्नति का आदेश रद्द किया गया था, उस समय रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक जांच लंबित नहीं थी। निम्नलिखित टिप्पणियाँ वर्तमान मामले के तथ्यों में अंतर और अनुपयुक्तता को स्पष्ट रूप से सामने लाती हैं: -

> यह आदेश सैन्य अधिकारियों को एक बार पदोन्नति के आदेश को रद्द करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं देता है। मेरे समक्ष यह भी स्वीकार किया गया है कि जिस समय पदोन्नति का आदेश रद्द किया गया था उस समय याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक जांच लंबित नहीं थी और इस आधार पर भी याचिकाकर्ता के मामले में सेना आदेश 236/73 लागू नहीं होगा। यह मानते हुए भी कि नहीं, सेना आदेश 236/73 में कानून की कुछ शक्ति है। मेरी राय है कि यह बात वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है। भले ही यह आदेश लागू हो, इसका उपयोग केवल याचिकाकर्ता के खिलाफ यूनिट से बाहर उसकी पोस्टिंग के खिलाफ किया जा सकता था और उसके पक्ष में किए गए पदोन्नति के आदेश को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता था।"

वर्तमान मामले में, जब याचिकाकर्ता को 15 अप्रैल, 1985 से मुख्यालय 39 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड से जोड़ा गया था, तो उचित अदालत की जांच के बाद कार्रवाई की गई थी और सक्षम प्राधिकारी ने निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। पूछताछ के बाद पीतल और एल्युमीनियम स्क्रैप की अवैध बिक्री में उनकी संलिप्तता

स्थापित होने के बाद मुख्यालय 39 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड से उनका जुड़ाव किया गया था। अपीलकर्ताओं की कार्रवाई कानून के तहत पूरी तरह से उचित है।

मेजर सीके पर भी गहरी निर्भरता रखी गई। डी. में आईपी गुप्ता यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (3) को रखा गया। उस मामले में, विवाद निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ: रिट याचिकाकर्ता को फरवरी से कार्यवाहक लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया था। 27, 1975. 22 मार्च, 1976 को, उन्हें ब्रिगेड कमांडर द्वारा सैन्य अस्पताल, किर्की के ऑफिसर कमांडिंग को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था। मनोरोग परीक्षण और रिपोर्ट। 23 मार्च, 1976 को, मनोचिकित्सा में विशेषज्ञता प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल ए. मुखर्जी द्वारा उनकी जांच की गई और 26 मार्च, 1976 को, भारतीय नौसेना के सलाहकार (मनोचिकित्सा) सर्जन कमोडोर टी.बी.डी.नेटो द्वारा उनकी जांच की गई। विशेषज्ञों द्वारा जांच के परिणामस्वरूप, 13 अगस्त 1976 को उनके चिकित्सा वर्गीकरण को SHAPE-SI (सभी कर्तव्यों के लिए उपयुक्त) से घटाकर SHAPE S. 3-T.24 (उन क्षेत्रों में पर्यवेक्षण के तहत नियमित कर्तव्यों के लिए उपयुक्त) कर दिया गया जहां अस्पताल हैं। पास में ही मनोचिकित्सीय सुविधाएं मौजूद हैं, जो उच्च ऊंचाई पर कर्तव्यों के लिए उपयुक्त नहीं हैं)। 14 मई 1976 को एक अटैचमेंट ऑर्डर द्वारा, उन्हें 4/3 गोरखा राइफल्स से मुख्यालय 54, इन्फेंट्री डिवीजन में कमांडर एनसीसी ग्रुप मुख्यालय बेल्लारी के पद पर कार्यवाहक लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था। वह 14 अगस्त, 1976 को छुट्टी से लौटे और 16 नवंबर, 1976 तक मुख्यालय 54 इन्फैंट्री डिवीजन से जुड़े रहे। 16 नवंबर, 1976 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता, जिसे आदेश में कार्यवाहक लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में वर्णित किया गया था, को "जीएलओ" के रूप में तैनात किया गया था। मेजर/कैप्टन) 142, जीएल सेकंड टाइप सी वाइस कैप्टन। आई.के. बेदी” जाहिर तौर पर जिस पद पर याचिकाकर्ता को 16 नवंबर 1976 के आदेश द्वारा स्थानांतरित किया

गया था, वह एक ऐसा पद था जिसे मेजर या कैपिटन रैंक का कोई अधिकारी संभाल सकता था और वास्तव में यह उस समय एक अधिकारी के पास था जो कैप्टन के पद का था। हालाँकि याचिकाकर्ता के पद को कार्यवाहक लेफ्टिनेंट कर्नल से घटाकर मेजर के पद तक विशेष रूप से कम करने का कोई आदेश नहीं है, लेकिन 16 नवंबर, 1976 के पोस्टिंग आदेश को ब्रिगेडियर प्रभारी और अन्य सभी सेना अधिकारियों द्वारा ऐसा ही माना गया था और याचिकाकर्ता को ब्रिगेडियर द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के बैज न पहनने का निर्देश दिया गया। इस आदेश को रिट याचिका में चुनौती दी गई और शीर्ष न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ रिट याचिका को अनुमति दी: -

> "श्री खादर किसी भी नियम, आदेश या परिपत्र की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ रहे, जिसमें कहा गया था कि किसी अधिकारी को निचली चिकित्सा श्रेणी में रखने पर रैंक में कमी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। वास्तव में श्री खादर ने यह स्वीकार किया था कि जिस अधिकारी का मेडिकल वर्गीकरण डाउनग्रेड किया गया है, उस कारण उसका रैंक कम नहीं किया जाएगा, बल्कि वह पहले की तरह ही रैंक पर बना रहेगा। इसलिए, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि याचिकाकर्ता को रैंक में कमी क्यों करनी पड़ी क्योंकि उसकी पदोन्नति के बाद उसका मेडिकल वर्गीकरण डाउनग्रेड कर दिया गया था।

उपरोक्त टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों में अंतर और इसकी प्रयोज्यता को दर्शाती हैं। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस आशय के सकारात्मक निर्देश हैं "जैसे कि जब कोई अधिकारी इक्कीस दिनों के लिए किसी विशेष नियुक्ति में अनुशासनात्मक आधार पर संलग्न होने के कारण या अस्पताल में भर्ती होने के कारण बीमारी के कारण अप्रभावी हो जाता है, तो वह कार्यवाहक पद छोड़ देता है।" वह अब उन कर्तव्यों का पालन नहीं

कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें अभिनय पद दिया गया था।" अधिकारियों की कार्रवाई इन निर्देशों के अनुसार सख्ती से की गई है और इसलिए, इसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

(11) पूर्वगामी कारणों से, एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया जाता है, अपील की अनुमति दी जाती है और रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

आर.एन.आर.

पहले: जी. सी. मितल और एस. एस. सोढ़ी, जे.जे.

केशो राम खुशी राम,–निवेदक

बनाम

आयकर आयुक्त, हरियाणा, - प्रतिवादी।

1982 का आयकर संदर्भ संख्या 23

6 अप्रैल, 1989.

आयकर अधिनियम (1961 का XLIII) धारा 271(एल)(सी) - निर्धारिती ने निर्धारित आय का 80 प्रतिशत से अधिक रिटर्न दिया - जुर्माना लगाने के लिए विभाग पर सबूत का बोझ - विभाग निर्धारिती पर बोझ डाल रहा है - कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया निर्धारिती द्वारा–विभाग द्वारा निर्धारिती पर जुर्माना लगाना–ऐसा लगाना–चाहे कानूनी हो।

माना गया कि हमारा विचार है कि ट्रिब्यूनल निर्धारिती पर सबूत का गलत बोझ डालकर जुर्माना बरकरार रखने में सही नहीं था। तदनुसार, निर्धारिती की अपील को नए सिरे से सुनने और कानून के अनुसार विभाग पर बोझ डालने के बाद नए निर्णय लेने के लिए मामला ट्रिब्यूनल को वापस भेजा जाता है।

(पैरा 3).

आयकर अधिनियम की धारा 271(एल)(सी) के तहत संदर्भ। 1961 आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ द्वारा, आईटीए में 13 मई, 1981 के न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के निम्नलिखित प्रश्नों पर राय के लिए माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को। 1979 की संख्या 895, निर्धारण वर्ष 1974-75 :

"क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल ने रुपये का जुर्माना कायम रखने में कानूनी गलती की है। आयकर अधिकारी द्वारा आयकर अधिकारी द्वारा आयकर $ टीजीएक्स अधिनियम, 1961 की धारा |271(एल)(सी) के तहत लगाया गया 9400?"

(1) A.I.R. 1967 S.C. 1910.

(2) 1977 (2) C.L.R. 865.
(3) A.I.R. 1983 S.C, 1122,

<u>अस्वीकरण:</u> स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा